17.31 hrs.

Title: Discussion on points arising out of the answer given by the Minister of State in the Ministry of Small Scale Industry, Agro and Rural Industies to Starred Question No. 245 of 8.8.2001 regarding Dereservation in the Small Scale Sector.

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विाय पर आपने मुझे आधे घंटे की चर्चा करने के लिए मान्यता दी। देश के सभी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ से और उसमें काम करने वाले कामगारों की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूं। देश में जो भी प्रोडक्शन होता है, उसमें 40 परसैंट प्रोडक्शन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज करती हैं। वहां उच्च क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है। एसएसआई यूनिट्स ने एक्सपोर्ट 34 से 35 परसैंट एचीव किया है। खास करके देश में 1.75 से दो करोड़ लोगों को रोजगार स्माल स्केल इंडस्ट्रीज देती हैं।

17.32 ण्द्धद्द (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक महत्वपूर्ण महकमा है। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर और खास तौर पर डबल्यूटीओ के प्रेशर में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की कुछ इंडस्ट्रीज रिजर्व की गई थी लेकिन उसे अब यह डि-रिजर्ब करने जा रहे हैं। देश में पिछले कुछ सालों से हर स्टेट में हजारों-हजार इंडस्ट्रीज जिन्हें इंडस्ट्रियल डेवलपमैंट कारपोरेशन के माध्यम से चलाया जाता है इसके कारण वहां की यूनिट्स बंद होती जा रही हैं, कामगार बेकार हो रहे हैं। आज के हालात में मंत्री महोदय ने 8 अगस्त को मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। उसमें उन्होंने बताया कि खास करके 15 यूनिट्स में से 14 यूनिट्स को डि-रिजर्व किया गया। इस मामले में उन्होंने अपनी सफाई दी। उस दिन हाउस में कम समय होने के कारण मंत्री महोदय इस प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दे पाईं लेकिन हमने उस दिन मंत्री महोदय का शुक्रिया अदा किया था। आज भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कैबिनेट ने आडवाणी जी की अध्यक्षता में जो ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई थी उसमें माननीय वित्त मंत्री, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर, टैक्सटाइल मिनिस्टर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की मिनिस्टर मैडम जी भी थी। डिसकसशन के समय मैडम ने 14 इंडस्ट्रीज के डि-रिजर्व करने की बात को अपोज किया था। देश में पहले ही लाखों-लाख मजदूर बेकार हो चुके हैं और हजारों इंडस्ट्रीज हर स्टेट में बंद हो चुकी हैं। यह निर्णय देश और जनता के हित में नहीं होगा लेकिन चार कैबिनेट मिनिस्टर्स वर्सिज एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर उनको फेस नहीं कर पाईं और 14 इंडस्ट्रीज डि-रिजर्व कर दी गईं जिस में खास तौर पर गारमैंट्स, टैक्सटाइल और लैदर से बनी चीजें आती हैं। इन चीजों को मल्टीनैशनल ग्रैप करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। इतनी बड़ी साजिश इस देश में वे लोग कर रहे हैं।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर हमने उचित समय रहते देश की स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को नहीं बचाया और उन पर कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में इस देश में ये स्माल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म हो जायेंगी। मैं महाराट्र राज्य से आता हूं जहां लाखों मजदूर इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ये इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर एक्पोर्ट ओरिएंटेड मैटीरियल पैदा करती हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को कठोर निर्णय लेना चाहिये।

सभापति जी, जब 1991 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, नेता विरोधी दल थे और इधर वाली इन बैंचों पर बैठा करते थे, वह तत्कालीन वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह के पास एक डेलीगेशन लेकर गये थे। उनके साथ श्री आडवाणी के अलावा एस.एस.आईज़ एसोसिएशन के पदाधिकारी भी थे। उस समय श्री वाजपेयी ने साफ तौर पर डा. मनमोहन सिंह से कहा था कि सरकार की इकौनोमिक पालिसी की वजह से देश के लाखों-लाख यूनिट्स बंद हो रहे हैं और कम्पटीशन की हालत में नहीं हैं। लेकिन जब देश के एक वरिठ नेता प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने अपनी बात पलट दी। आज कैबिनेट की सब-कमेटी के माध्यम से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से देश की सभी ऐसी स्माल स्केल इंडट्रीज , जो रिजर्व केटेगरी की हैं, को डी-रिजर्व किया जा रहा है।

सभापति महोदय, देश के अंदर के.वी.आई.सी. के अंतर्गत काम करने वाली जितनी खादी इंडस्ट्रीज हैं, उनका राट्रीय महत्व है क्योंकि आजादी की लड़ाई के समय खादी एक राट्रीय मुद्दा रहा है, उस इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिये विदेशी कम्पनी को कंसलटेंट अपाइंट किया गया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, यदि हां तो केन्द्र सरकार खादी इंडस्ट्रीज के लिये कितना फंड देना चाहती है और देश में कितने लोगों को इसके माध्यम से रोज़गार उपलब्ध होंगे?

सभापति महोदय, सरकार ने ओपन जनरल लाइसेंस के अंदर 642 आइटम्स डी-रिजर्व किये जाने का बीड़ा उठाया है। आज कोई भी आदमी फ्रीली इम्पोर्ट कर सकता है। ओ.जी.एल. के अंतर्गत चाइना, ताइवान, फिलीपाइन्स जैसे देशों से मंगाकर बड़े पैमाने पर मैनुफैक्चरिंग गुड्स यहां सस्ते दामों पर बेची जा रही हैं। इस कारण हमारे देश के स्माल स्केल यूनिट्स बंद होने जा रहे है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि नेपाल के बार्डर से चीन, ताइवान या दूसरे देशों से जो अवैध रूप से इंडस्ट्रियल गुड्स आ रहे हैं या ओ.जी.एल. के नाम पर इम्पोर्ट कर रहे हैं, उन पर रोक लगाने के लिये या ड्यूटी बढ़ाकर एस.एस.आईज. को बचाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? अगर देश में इन उद्योगों को जिन्दा रखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस इंडस्ट्री को हम एम.एन.सीज़ के कम्पीटीशन में उतार रहे हैं और जो बैंकों या फानेंशियल इंस्टीट्युशन्स से 5-6 परसेंट इंटरैस्ट पर कर्ज लेकर अपनी मैनुफैक्चरिग करते हैं, उनसे 16 या 18 परसेंट इंटरैस्ट पर बैंक लोन लेकर यहां के एस.एस.आईज़ के एंटरप्योनोर्स कैसे कम्पीट कर पायेंगे? उन लोगों को क्या सहूलियतें देना चाहते हैं? आपने अपग्रेडेशन या माडर्नाइजेशन करने के लिये 25 लाख की लिमिट रखी है, क्या उसे बढ़ाना चाहते हैं?

सभापति महोदय, सरकार ने श्री एस.पी.गुप्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, क्या उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, यदि हां, तो उसने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को प्र ाफिट में लाने के लिये क्या क्या सुझाव दिये हैं। उसी तरह से एस.एस.आईज़ एसोसिएशन ने अपने विचार सरकार के सामने रखे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहा था कि अगर सरकार ने एस.एस.आईज़ को एम.एन.सीज़ के कम्पीटीशन में उतारना है तो पहले मार्किट के लिये उचित माहौल बनाये, सुविधायें दें और बाद में इन इंडस्ट्रीज को डी-रिजर्व करें। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक कितनी इंडस्ट्रीज रिजर्व रखी गई हैं?

फाइनेन्स मिनिस्टर अपनी स्पीच में कह चुके हैं कि आने वाले समय में हम सौ प्रतिशत डीरिजर्व करने जा रहे हैं। अगर सौ प्रतिशत डीरिजर्व होता है तो हमारे देश के स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत तकलीफ में आयेंगे। अगर हमें उन्हें बचाना है तो आपको उनकी मदद करनी होगी ।

सभापति महोदय, अब मैं एन्सीलियराइजेशन के बारे में कहना चाहता हूं। मंत्री महोदया हमारे देश में जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनके माध्यम से जो हमारी एन्सीलियरी यूनिट्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए क्या केन्द्र सरकार ने कोई योजना बनाई है और इसमें राज्यों में एन्सीलियरी यूनिट्स को जो बड़ी चीजें लगती हैं, वे एन्सीलियरी यूनिट्स से उसी एरिया से खरीदी जाएं, क्या आप इसके लिए कोई कानून बनाने जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि इस विाय पर सदन के सभी माननीय सदस्य चाहे वे किसी भी पार्टी या ग्रुप के हों, सबका एक मत होगा कि भारत में पिछले पचास सालों में हमारे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को जो मजबूती मिली है, उसे खत्म होने से बचाया जाए। मैं मंत्री महोदया से उम्मीद करता हूं कि आप इसमें कोई ठोस निर्णय लेकर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगी। धन्यवाद ।

डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, विाय अत्यंत गम्भीर है। लघु उद्योगों के संरक्षण के बारे में जो प्रश्न उठाया गया है, उस बारे में मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति या योजना तैयार की है जिसके अनुसार वे वस्तुएं जो लघु उद्योगों में बनती हैं, वे बड़े

उद्योगों में न बनें और बड़े उद्योगों से उन्हें विभाजित करके रखें। क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव या योजना सरकार ने बनाई है या नहीं । आज लघु उद्योगों को संरक्षण की जरूरत है ।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि लघु उद्योंगो को मिलने वाले ऋण में अत्यधिक देरी होती है, जिसके कारण लघु उद्योंगों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता है और वे कम्पिटीशन में खड़े नहीं हो पाते हैं। इस प्रतिस्पर्धा को बचाने की दृटि से समय पर उन्हें ऋण की सुविधा या अन्यान्य सुविधाएं मिलनी चाहिए और उनका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। जिस प्रकार से कई राज्यों ने इनके लिए एक खिड़की योजना तैयार की है, क्या आप भी उन राज्यों की तरह से कोई ऐसी योजना तैयार करने का विचार रखती हैं । अन्यथा जैसे बड़ी-बड़ी कम्पनियां आज कम्पिटीशन में खड़ी हो गई हैं और छोटी-छोटी वस्तुएं जैसे सुई, साबुन और खाद्य सामग्री बनाने का काम मल्टी नेशनल कम्पनियां करने लग गई हैं, उसके कारण हमारे छोटे उद्योग अपने आप बंद होते चले जा रहे हैं या बंद होने के कगार पर हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धा में वे टिक नहीं सकते। ऐसी स्थिति में इनके संरक्षण की दृटि से क्या आप कोई समेकित योजना तैयार करने का विचार रखती हैं, ताकि इन्हें बचाया जा सके और जो लघु उद्योग हमारे देश की आर्थिक उन्नति में सहायक हैं, वे भविय में भी इसी प्रकार से हमारी आर्थिक उन्नति में सहयोग देते रहें।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : छोटे उद्योंगो की चिन्ता के संदर्भ में आज यह आधे घंटे की चर्चा का प्रस्ताव सदन मे लाया गया है। महोदय, एक तरफ एक दृश्य पैदा होता है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में जितने छोटे उद्योग हैं वे रुग्ण अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर सही रूप से आंकड़ों को देखें तो कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें अपने आपमें एक विरोधाभास है। क्योंकि जब आंकड़ों की तरफ ध्यान जाता है तो उसमें स्पट हो जाता है कि अगर हम लोग कुछ आंकड़ों को देखें तो जो सरकारी आंकड़ें हैं वे सर्वे के आधार पर आये हैं। छोटे उद्योंगों में पिछले 1990 से 1999 तक जो बढ़ौत्तरी हुई है और जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ा उसमें उन्नति हो रही है, यह अपने आपमें सराहनीय है। भारत की मूल उत्पादकता में छोटे उद्योगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम मूलत: इस बात को समझने का प्रयास करें कि जो भी कमियां है उनकी तरफ सरकार का ध्यान केन्द्रित करते हुए हम लोग इस सैक्टर को रुग्ण अवस्था का सैक्टर न मानें तो उचित होगा । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकृट करूंगा कि आज की तारीख में प्राइस में टोटल आउटपुट 527 हजार करोड़ रुपये है, यानी 527 हजार करोड़ रुपये की उत्पादकता छोटे उद्योंगो के द्वारा की जाती है । हमारे देश में 49 हजार करोड़ रुपए उनके एक्सपोर्ट पर व्यय होता है । यह आंकड़ा खुद दर्शाता है कि आज भारत जैसे बड़े देश में इन छोटे उद्योंगों के कितने मायने हैं। मैं कम्पैरेटिव ग्रोथ रेट के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन यह एक और विश्लेाण का विाय बन सकता है कि पूरे भारत में जितना एन.पी.ए. है और जो इंडस्ट्रियल सैक्टर है â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं पृठभूमि बता रहा हूँ।

सभापति महोदय : आप नियम देखिये, पृठभूमि मत बताइए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं प्रश्न तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूं पृठभूमि बताकर। मेरे दो-तीन प्रश्न हैं। एक भाग का भी उत्तर हो जाए तो पर्याप्त रहेगा।

क्या माननीय मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी उद्योग संबंधित कई मंत्रालयों का संसर्ग इन उद्योगों से है? क्या अकेले एस.एस.आई. की जिम्मेदारी है उसकी शक्ति बढ़ाने, उसकी क्रैडिट फैसिलिटीज़ बढ़ाने की? क्या अकेली जिम्मेदारी यह आपके विभाग की है या अनेक विभाग जो भारतर्वा में हैं, छोटे उद्योग उन विभागों पर भी निर्भर हैं या उनकी इस संदर्भ में कोई भूमिका है? क्या हमारे पास वैसे बैंकों या फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स को प्रोत्साहन देने का कोई प्रावधान है जो सचमुच में इस क्षेत्र में आगे बढ़कर ऐसे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि हम उनकी क्रैडिट रेटिंग को बेहतर मानें और उनके कार्यकलापों को बेहतर समझें? मैं इस बात पर भी स्पटीकरण चाहूंगा कि क्या आवश्यकता है और अगर आवश्यकता है कि WTO के पश्चात् जहां प्रतिस्पर्द्धा हर स्तर पर उत्पन्न हो रही है, अपनी सरकार की तरफ से इस प्रतिस्पर्द्धा को कायम रखने के लिए, इसे मजबूत बनाने के लिए ताकि छोटे निर्माताओं को, छोटे उद्योग वालों को सफलता प्राप्त हो सके, प्रोत्साहन मिल सके, इसके प्रति सरकार का क्या रुख है?

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Sir, I would like to ask a pointed question to the hon. Minister.

सभापति महोदय : विशेा अनुमति के तौर पर आप एक ही प्रश्न पूछिये। वैसे रूल परमिट नहीं करता है।

SHRI M.V.V.S. MURTHI : The situation will aggravate with dereservation of small scale industries because carpets and toys are manufactured as a cottage industry and home industry in certain places like Eluru and Etikoppata of Andhra Pradesh. It is so everywhere in the country. Employment situation will get aggravated. As it is, we are facing unemployment problem. How will the hon. Minister ensure employment with this dereservation of small scale industries?

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर) : छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालीन ऋण और कम ब्याज पर ऋण क्या शासन उनको देगा?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES, AGRO AND RURAL INDUSTRIES, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING, DEPARTMENT OF PENSIONS AND PENSIONERS WELFARE OF THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): Sir, I think, basically all the questions have already been taken care of by the hon. Member, Shri Puglia because in his opening remarks, he has covered every single piece of ground which he wanted to, as far as small scale industry is concerned.

I am actually very pleased that a discussion of this nature is taking place because it is concerning a very important sector. Everyone is concerned with this across the board. The issue that has sparked this off is actually that of dereservation. But before I touch upon that point, I would just want to make one point. There is misinformation that is doing the round that the small scale industry is in extremely bad situation and in its last throes, and that it would not last long. I think this is a very dismal way of looking at things because if you look at the figures referred to by Shri Rudy, the hon. Member, it is very clear that the sector is very vibrant and reinventive. When everytime it finds itself in a particular kind of a situation, it reinvents itself due to its size and is able to continue with whatever

business it needs today.

I would like to say here that when this issue of dereservation started taking place, we looked at the figures of 1997 and those of the last year. The number of items were 15, and 14 had been dereserved. Over a period of time, we have 799 such items which still remain reserved today.

We have commissioned an independent study to look at the impact of the dereservation of those 15 items that happened in 1997. We found that there was no negative impact of dereservation of those particular items. I would just like to look at the brighter side of the things. We do not do any of these things without actually taking into consideration the views of the stake holders. And it is only after the discussion with the stake holders, we went ahead with the dereservation of those items.

Hon. Member, Shri Puglia, asked not only about dereservation of these 14 items but also spoke about imports from China and the effect that imports from China has had upon this particular sector. I would like to say that we have opened up the economy as a result of various agreements that have come under the aegis of WTO. Therefore, there is going to be some kind of an impact. This is not something that we can run away from. We have to take into account the fact that we would be facing a tough task and that we would be exposed to certain amount of competition. But there would be infusion of capital and technology. There is going to be an opportunity to expand. Therefore, we can reap the benefits of economies of scale. At the same time, certain protections are available to take away the negative impact of liberalisation. We will be able to enhance the applied rates to the bound level. There are something called anti-dumping duties. There are safeguard measures if any injury is caused by sudden and massive surge of imports. There is a protection to human, animal, and plant health. There is a question of security of nation. You can impose the same standards applicable to domestic industry and QRs can be re-applied if we find that we have some problems.

As far as discontinuation of reservation policy is concerned, the reservation policy is compatible with the WTO and it is an instrument of support to the small industry. This will continue but we will be reviewing the items on the list. It is not that for the first time these items have been dereserved. We did all this with the full consultation of the stake holders. As far as China is concerned, I need to tell you that Indian export to China grew by 46 per cent whereas imports from China grew by only 20 per cent. These are figures which are easily available. Out of the 95 cases since 1992, anti-dumping investigations are on in 44 cases against China. Recently, duty has been imposed on sports shoes and dry cell batteries that come from China. Toys have actually been dropped for lack of evidence. So, the situation is not as bad as everyone makes it out to be. Small industries have a special place and we intend to be supportive to them because our Ministry is really a facilitative Ministry. Our job is not to be in the business for doing business. We are trying our very best to put in supportive measures and those measures were announced by the hon. Prime Minister on 30th July.

MR. CHAIRMAN : Shri Nitish Sengupta, please take your seat. ...(*Interruptions*)

SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: Small industries have a special place. There is a niche market for them which nobody else can fill. Small industries would always be relevant because of the fact that they are small enough to be able to move along as far as possible. There is a niche market which they are going to fill. Nobody is going to take that away from them. They can also, as I said, take into account the economies of scale.

I would just like to quickly mention the kind of support that we have been able to give very recently. The Gupta Committee made very good recommendations. I would be happy to give a copy of the Gupta Committee

Report to the hon. Members so that they can have a look at it. Very good recommendations came out of it. Two important lines have been taken. One is about the money that we are putting in towards the upgradation of technology.

The other one is the Credit Guarantee Scheme which we have put into being because we feel that the most important thing today for the small scale industry is to have credit support. Now, I think, with the coming into being of the Credit Guarantee Trust, this is going to be taken into account as well as the upgradation of technology towards which we have set aside a considerable amount of money.

There are major ongoing schemes. As I said, the Credit Guarantee Scheme itself is for the individual SSIs. It gives the collateral free composite loan up to Rs.25 lakh. Then, there is a Credit Linked Capital Subsidy Scheme for Technology Upgradation where a capital subsidy of 12 per cent is given on loans taken for technology upgradation. This again is for individual SSIs. Then, we have the ISO-9000 Certification Reimbursement Scheme. It is a reimbursement scheme. Costs of obtaining ISO-9000 Certification are reimbursed to the extent of 75 per cent or Rs.75,000 whichever is lower for the individual SSIs.

Then, we have the U PTECH Scheme which is a very useful Scheme. This promotes technology upgradation and

also allows for putting up common facility centres for SSI units of one industry. The Scheme is basically for a cluster of similar SSI units.

Then, we have the Purchase and Price Preference Policy. Under the Single Point Registration Scheme of NSIC, 358 items are reserved for exclusive purchase from SSI by the Central Government.

Then, there is the PMRY Scheme. Loan up to Rs.2 lakh with a subsidy of 7.5 per cent is given. Then, there are Testing Centres for which we give an assistance of 50 per cent or Rs.50 lakh whichever is less. These are available for associations. Then, there is the Integrated Infrastructure Development Scheme. An assistance of 40 per cent or Rs.2 crore is given, whichever is less, for setting up of industrial estates for the SSI units. For the North-East, the assistance is 80 per cent or Rs.4 crore. Then, there are Mini Tool Rooms. An assistance of 90 per cent or Rs.9 crore is given, whichever is less, for setting up of Mini Tool Rooms. For upgradation of existing Tool Rooms, an assistance of 75 per cent or Rs.7.5 crore is given. I think the assistance that is being provided is considerable.

This Ministry itself has come into being only two years ago. The package was announced only last year. I think that we do need to fairly actually give that kind of time to be able to see how the support systems are going to work.

About the Dr. S.P. Gupta Report, I would submit that I shall be handing it over to you at a later time so that you can have a look at it.

Basically, you have also spoken about Khadi. Actually, you covered everything. This is a very large and wide subject. I would be able to extensively discuss it with you. But I think in the interest of time, perhaps, I am trying to shorten this. About Khadi, I submit that you particularly asked me why did I go for a foreign consultant. I can understand the reason for having this consultant. Without being apologetic about it, I would like you to know that it is an Indian subsidiary of Arthur Anderson itself. It is being manned entirely by an Indian Group at this moment. But, apart from that, it has done consultancy for very prestigious institutions like the RBI, the petroleum companies, for the SEBs and for various banks. I think it has done very well for them.

What we really required was not actually to tell us about people knew about Khadi sector. But what we looked at was actually programmes regarding investment and improvement of the actual body when you go into the new millennium. That is what we are looking at. We are not looking at it to see any kind of improvement for the Khadi sector itself because there are lots of bodies within the country which know about this sector and which are giving us very vital inputs. It is a very important sector. We are very much concerned about it. The Government is doing its very best to be able to put as much effort towards the growth of this sector as possible.

Together Khadi and Village Industries, these industries are producing about Rs.5000 crore worth of goods. I think it is an amazing amount. With a little bit of push and support from the Government itself, we will be able to do much more.

Dr. Pandeya asked a question which was very much similar to that of Shri Pugalia's. I think at the end of the day, I will repeat that they will have to face up to competition. They will have to improve quality because the WTO and the liberalisation regime is not something that is concerning just India but it goes across the globe. I think, therefore, this is something that everybody has to put up with. We will have to be able to pull up our socks to take care of technology and do whatever we can to see that the sector is strengthened so that it can go ahead and face the new millennium.

18.00 hrs.

Shri Rajiv Pratap Rudy came up with very good ideas. It is not that my Ministry alone that takes care of it. My Ministry really is a nodal agency. We try to facilitate all this and try to make it easier for the small-scale sector. The Ministry of Agriculture, the Ministry of Finance, the Ministry of Information Technology, the MNES and a lot of other Ministries converge upon this sector. It is important that we have a look at the suggestion that was made by the hon. Member. As far as the convergence, banks and the incentives are concerned, it is a very good idea. We will certainly look at it. ...(*Interruptions*)

As far as WTO and the packages are concerned, I have just mentioned to you that yes, there is a protection that is available but we have to work within certain parameters. We are doing that. We have to put into place, things like War Room in the Commerce Ministry. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRIMATI VASUNDHARA RAJE : We are actually monitoring the impact of the QRs. Out of 300 items which we are monitoring, 67 items are of interest to SSI.

As far as anti-dumping is concerned, India is a country which is taking the least amount of time to initiate anti-

dumping activities, cases and investigations. It is the second biggest user of anti-dumping investigations after South Africa.

I mentioned to you a number of cases that have been registered. We are also trying our level best to sensitise the small-scale sector across the country. As far as the WTO is concerned, we have held 28 seminars across the country, talked to the associations and tried to involve them in getting the people understand what this is all about. Similar is the case with regard to the Intellectual Property Rights. At the end of the day, this is a very close activity between the individual entrepreneur, industries, associations, the State Governments and the Central Government. I think, here, there are really no parties involved. It is something that confronts all of us. We are interacting at close quarters with all these people to try and build a substantial base for the improvement of this sector in the country.

I do not have a magic wand. I do not think that the Government has a magic wand and nobody has to be able to say that things are going to improve radically overnight. This is an amazing sector. There are people who have closed down their units. There are new start-ups. I just want to give a small figure.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: According to the RBI figures, last year, perhaps, there were over three lakh sick industries but at the same time, we have figures which tell us that under the PMRY, new start-ups of almost two lakh industries across the country are taking place every year. So, actually there are no figures as such which are Centrally-maintained about this. The figures which come from the State Government and associations are put together at the moment in the form of census/sample surveys which would give us a basic idea of as to where the sickness lie and as to what are the sectors that need to be supported. We will be more supportive of them in times to come.

Frankly, I think it is a major effort, and it is an effort that cannot be made just by the Government alone. I look forward to the support of all Members. I am open to suggestions. I would be happy to turn and talk with Members if there is anything that needs to be looked into and taken care of.

I can only thank all of you − Shri Naresh Puglia, Dr. Laxminarayan Pandeya, Shri Rajiv Pratap Rudi and Shri M.V.V.S. Murthy - for having taken such a keen interest in the affairs of the small-scale industry. I also thank Shri Priya Ranjan Dasmunsi who has made his contribution. I would only be too happy to say that if there is anybody who needs to know or wants to contribute or wants to talk about and discuss the sector, I shall be happy to do it. Thank you very much.

â€¦â€¦â€¦â€¦..